

ESZ अधिसूचना के खिलाफ केरल का वरिध प्रदर्शन

प्रलम्बिस के लयि:

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986, राष्ठीरय वन्यजीव कार्ययोजना, राष्ठीरय उदयान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण वन ।

मेन्स के लयि:

जैववविधिता और इसका संरक्षण, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986, राष्ठीरय वन्यजीव कार्ययोजना ।

चर्चा में क्यौं?

केरल में कसिान [पर्यावरण संवेदी क्षेत्र \(ESZ\)](#) स्थापति करने के [सर्वोच्च न्यायालय](#) के आदेश का वरिध कर रहे हैं ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने [राष्ठीरय उदयानों और वन्यजीव अभयारण्यों](#) सहति प्रत्येक संरक्षण वन की सीमांकति सीमा से न्यूनतम एक कलिमीटर तक के क्षेत्र को अनविरय रूप से ESZ घोषति करने का नरिदेश दयिा है ।
- केरल राज्य वधिानसभा ने केंद्र से राज्य सरकार के प्रस्तावों पर वधिार करके ज़ोन्स को अधसूचति करने की मांग की है, जसिमें [राज्य के लगभग 10 संरक्षण क्षेत्रों को शून्य ESZ के रूप में चहिनि कयिा गया है](#) ।

इको सेंसटिवि ज़ोन:

- **परचिय:**
 - [पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#) की [राष्ठीरय वन्यजीव कार्ययोजना \(2002-2016\)](#) ने नरिधारति कयिा कि [पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986](#) के तहत राज्य सरकारों को राष्ठीरय उदयानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कलिमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसटिवि ज़ोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) घोषति करना चाहयि ।
 - जबकि 10 कलिमी. के नयिम को एक सामान्य सदिधांत के रूप में लागू कयिा जाता है, इसके आवेदन की सीमा भनिन हो सकती है ।
 - वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से 10 कलिमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधसूचति कयिा जा सकता है, यदािे पारसिथतिकि रूप से महत्त्वपूर्ण ["संवेदनशील गलियारे"](#) हैं ।
- **महत्त्व:**
 - ESZs को [संरक्षण क्षेत्रों के लयि "शॉक एबजॉरबर"](#) के रूप में बनाया गया है ताकि आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों के ["कमज़ोर पारसिथतिकि तंत्र"](#) पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कयिा जा सके ।
 - ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे ।
 - ESZ का उद्देश्य आस-पास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है, बल्कि संरक्षण क्षेत्रों की रक्षा करने और आसपास के वातावरण को परषिकृत करने में मदद करना है ।

पृष्ठभूमि:

- यह आदेश (Order) [पश्चिमी घाट पारसिथतिकि वशिषज्ञ पैनल \(WGEEP\)](#) की रपिर्ट (गाडगलि रपिर्ट) के एक दशक बाद आया है, जसिने राज्य में सामाजकि-राजनीतिक, आर्थकि और पारसिथतिकि आख्यानों को मौलकि रूप से प्रभावति कयिा था ।
 - हालाँकि यह WGEEP रपिर्ट से पहले के दनिों में राज्य द्वारा देखी गई उच्च-स्तरीय सार्वजनकि अशांति और वरिध के स्तर तक सीमति नहीं रहा बल्कि ESZ अधसूचना ने भी राज्यव्यापी वरिध शुरू कर दयिा है ।
- इससे पहले राज्य सरकार ने अपने मसौदा [ESZ अधसूचना के दायरे से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनकि संस्थानों को बाहर करने पर ध्यान केंद्रति कयिा था](#) ।
- पड़ोसी राज्यों के साथ वन सीमा साझा करने वाले संरक्षण क्षेत्रों के लयि ESZ का अंकन एक शांतपूरण मामला था क्यौंकि बीच में कोई मानव बस्ती नहीं थी ।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के हालयिा आदेश ने तस्वीर बदल दी है और राज्य सरकार को कम-से-कम दस संरक्षण क्षेत्रों के ESZ पर पुनर्वधिार

करने के लिये कहा गया है जनिहें पहले शून्य **ESZ** के रूप में चहिनति कयिा गया था ।

ESZ अधसूचना:

- इस अधसूचना से केरल में अपर्यि स्थति पैदा हो गई है जहाँ भूमि और भूमि उपयोग पैटर्न पर कसिी भी नयामक तंत्र का राजनीतिक प्रभाव होगा ।
- केरल अपने अनूठे परदृश्य पर संभावति प्रभाव को लेकर चतिति है ।
 - केरल में लगभग 30% वन भूमि है और पश्चिमी घाट राज्य के 48% हसिसे पर उसका कबज़ा है ।
- अधसूचति संरक्षति क्षेत्त्रों के पास मानव आबादी के उच्च घनत्व के कारण कसिान समूह और राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कसिभी मानव बस्तयिों को ESZ नयिमों से छूट दी जाए ।
- राज्य सरकार को आशंका है क सर्वोच्च नयायालय की अधसूचना से ज़मीनी स्थति और खराब हो सकती है क्योक इससे राज्य के हतिों पर तथा संरक्षति क्षेत्त्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहयि ताक दीर्घकालिक विकास को प्राप्त कयिा जा सके ।
- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधयिों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमति नहीं रखना चाहयि ।
- वनीकरण और अवक्रमति वनों का पुनर्वनीकरण, लुप्त आवासों का पुनरुद्धार, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दयिा जा सकता है ।
- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जनता के बीच इसके प्रतिकूल

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/kerala-s-protest-against-esz-notification>

